

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-2
संख्या-1072/IV(2)-श0वि0-14-34(सा0)/12
देहरादून : दिनांक 28 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा नगर निकायों के लिए स्वीकृत योजनाओं हेतु शासनादेश सं0-849/IV(2)-श0वि0-2015-34(सा0)/12, दि0-25.07.2015 के द्वारा 06 नगर निकायों को ₹ 3916.10 लाख अवमुक्त किए गए हैं। उक्त शासनादेश के बिंदू सं0-3(V) जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण इन्दिरा आवास योजना के पैटर्न पर लाभार्थियों के माध्यम से कराया जायेगा। तदक्रम में सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

- (1) कार्य की समयबद्धता के दृष्टिगत यदि लाभार्थी आवासों के निर्माण करने में समर्थ नहीं हैं तो प्रति लाभार्थी से इस आशय का अनुबन्ध नगर निकाय द्वारा लिया जाना होगा। इसके अतिरिक्त यदि उक्त नगर निकायों में से किसी नगर निकाय में लाभार्थी स्वयं आवास निर्माण कराना चाहते हैं तो वे निर्माण कार्य किये जाने हेतु स्वतंत्र होंगे।
- (2) यदि लाभार्थी की सहमति के आधार पर नगर निकाय आवासों का निर्माण करना चाहती हैं तो वे समयबद्धता, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता आदि हेतु सम्बन्धित नगर निकाय स्वयं उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों का सत्यापन थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एजेन्सी से कराया जाना होगा, कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

उक्त शासनादेश सं0-849/IV(2) -श0वि0-2015 -34(सा0)/12, दि0 25.07. 2015 को केवल इस सीमा तक संशोधन समझा जायेगा तथा शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

1072
संख्या- /IV(2)-श0वि0-14-15(सा0)/10, तददिनांक।

(डी0एस0 गर्बाल)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(ऑडिट) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव-शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/रूद्रप्रयाग।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, बड़कोट/भीमताल/केलाखेड़ा/शक्तिगढ़/सितारगंज/ऊखीमठ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।